



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 1990/भाद्रपद 6, 1912

No. 480]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 1990/BHADRA 6, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1990

का.आ. 660(अ) :—बैंकारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (7) के अनुसूचन में केन्द्रीय सरकार द्वारा 29 अगस्त, 1990 की तारीख को पूर्वाञ्चल बैंक लि., गुवाहाटी के मेल्ल बैंक आफ इंडिया से समामेलन की स्वीकृति के संबंध में, जो उक्त उपधारा के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गयी है, कठित तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th August, 1990

S.O. 660(F).—In pursuance of sub-section (7) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby specifies the 29th August, 1990 as the prescribed date in relation to the scheme for the amalgamation of the Purbanchal Bank Limited, Guwahati with Central Bank

2300GI/90

of India which has been sanctioned by the Central Government under the provisions of the said sub-section.

[No. 17/7/89-B.O.III(i)]

का. आ. 660(अ) :—केन्द्रीय सरकार ने बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन वि पूर्वाञ्चल बैंक लिमिटेड के संबंध में उक्त धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अधिस्थगन आदेश दिया है।

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेल्ल बैंक ऑफ इंडिया के साथ वि पूर्वाञ्चल बैंक लिमिटेड के समामेलन की योजना तैयार की है।

और रिजर्व बैंक ने उक्त धारा की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उक्त योजना का प्राप्य संबंधित बैंकों की भेजने के पश्चात् और उक्त योजना के संबंध में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात्, यह योजना मांगोपिती की है और उसे प्रवृत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें आये उल्लिखित विवरणों और शर्तों के प्रतीत इस योजना को प्रवृत्ति दे दी है।

(1)

(1) दि पूबोषल बैंक निमित्तेड अंतरक बैंक होगा और रेड्स बैंक ऑफ इंडिया अंतरिकी बैंक होगा ।

(2) ऐसी तारीख में जिसे केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करे (जिसे हमसे इसके पश्चात् विहित तारीख कहा गया है) अंतरक बैंक के सभी अधिकार अधिकारों, मांग, दावे, हित, अधिकार, शिष्टाधिकार, लाभ, सब और परिसर सहित श्रवण आस्तिया और संपत्तियों जिसके अंतर्गत भू-धुनि को सभी प्रसंगियों या पट्टी या कगरीं द्वारा आरक्षित और उनमें अंतर्भूत किगये और अन्य धनराशियों और प्रसंगिकियों के अधीन परिसर, जिनके अधीन वे धारित हैं, इस योजना के अन्य उपधारा के अधीन अंतरक बैंक के कारोबार से संबंधित सभी कार्यालय, पर्तोंवर, छत्ते उपस्कर, संयंत्र, उपकरण और ताहिक, बड़ी, कागज-पत्र, लेखन-सामग्री स्टॉक, अन्य स्टॉक और अंशार, सभी स्टॉक संबंधी निवेश, शेयर और प्रतिभूतियां, प्राप्त सभी जेय और सार्वजन्य हंडियां, बैंक दलियत सहित सभी शेष और बाट या जमाखाने में नकदी (मांग पर या अन्य सूचना पर प्रतिदय राशि सहित, सभी बड़ी कृण, बंधक कृण और प्रतिभूतित लाभ सहित अन्य कृण या उसके लिए कोई प्रत्याभूति, सभी प्रत्याभूतियों के सभी अन्य संपत्तितगत अधिकार और आस्तितगत लाभ, यदि हैं, अंतरिकी बैंक को अंतर्भूत हो जाएंगे और उसकी संपत्ति और आस्तियां बन जाएंगे और विहित तारीख से ही अंतरक बैंक की सभी देयताएं, कार्य और बाध्यताएं, इससे उसके पश्चात् उपबंधित सीमा तक और रीति में अंतरिकी बैंक की देयताएं, कार्य और बाध्यताएं होंगी और बन जाएंगी ।

पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सभी संविदाएं, विलेय, बंधपत्र, करार, भुज्जतरतामें विधिक, अभियेदनों की मजूरियों और किसी भी प्रकार की अन्य लिखतें, जो विहित तारीख के ठीक पहले विद्यमान या प्रभावी हैं अंतरिकी बैंक के विरुद्ध या उसके पक्ष में इसमें धार्य उपबंधित सीमा तक और रीति में प्रभावी होंगी और जैसे ही कार्यान्विता की जाएंगी, मानो अंतरक बैंक के स्थान पर अंतरिकी बैंक उसमें पक्षधार रहा हो, मानो वे अंतरिकी बैंक के पक्ष में जागी की गयी हों ।

यदि विहित तारीख को अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अपील या किसी भी प्रकार की कोई अन्य विधिक कार्यवाही लखित हो तो उसका उपशमन नहीं होगा वह बर नहीं होंगी या उस पर किसी भी रूप से प्रतिवक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु वह इस योजना के अन्य उपबंधों के अधीन अंतरिकी बैंक के द्वारा या उसके विरुद्ध अभियोजित की जा सकेगी और प्रवक्त की जा सकेगी ।

यदि भारत ने बाहर के किसी देश की विधि के अनुसार इस योजना के उपबंध उस देश में स्थित किसी ऐसी आस्ति या देयता को जो अंतरक बैंक के उपक्रम के भाग है, अंतरिकी बैंक को अंतरित या उसमें निहित करने का प्रभाव स्वयं नहीं रखने को ऐसी आस्ति या देयता के संबंध में अंतरक बैंक का कार्यकाल विहित तारीख से अंतरिकी बैंक के तत्समय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी में स्थान हो जाएगा और वह कार्यपालक अधिकारी ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जो प्रभावी रूप से इसके कार्यकाल के प्रभावी परित्यमापन के प्रयोजन के लिए अंतरक बैंक द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी या की जा सकती है । मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा अंतरण और निहित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी सभी कार्यवाहिया करेगा, जो भारत के बाहर किसी ऐसे देश की विधियों द्वारा अपेक्षित हो और उस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या जो स्वयं या अपने द्वारा इस निर्माण प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा अंतरक बैंक की आस्तिया बसूल कर सकेगा या उसके दायित्व का निर्दहन कर सकेगा और उसकी श्रुत श्राव अंतरिकी बैंक को अंतरित कर सकेगा ।

(3) अंतरक बैंक की बहियां बंद की जाएंगी और उनकी तुलना की जाएगी और तुलन-पत्र प्रथमतः 14 जुलाई 1990 को कारोबार की समाप्ति पर तैयार किया जायेगा और उसके बाद निर्धारित तारीख से तुलन

पहले की तारीख को कारोबार बंद होने पर तैयार किया जायेगा और निश्चित तारीख से तुलन पहले की तारीख की स्थिति का तुलन-पत्र सार्वभौमिक या पारिष्ट कोषाचारों की किसी ऐसी पर्त द्वारा जो आरक्ष्य रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित या नामितरित की गयी हो लेया परीक्षित और प्रमाणित करण जायेगे ।

पूर्वगामी पैरा के उपबंधों के अनुसार तैयार किये गये अंतरक बैंक के प्रत्येक तुलन-पत्र की एक प्रति अंतरक बैंक द्वारा प्राप्त की जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत की जाएगी और तत्पश्चात् अंतरक बैंक से तुलन-पत्र या लाभ और हानि लेखा तैयार करने या उसे सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या उसकी प्रतियों कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करने या तुलन-पत्र और लेखों पर विचार करने के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 159 के उपबंधों के अनुपालन करने के लिए वार्षिक साधारण अधिदेयत सूचाने की श्रंभा नहीं की जाएगी और तत्पश्चात् अंतरक बैंक के निवेशक बोर्ड के लिए उस अधिनियम की धारा 285 की अपेक्षानुसार अधिवेशन करना आवश्यक नहीं होगा ।

(4) (1) अंतरिकी बैंक अंतरक बैंक के परामर्श में निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अंतरक बैंक की गतियों और आस्तियों का मूल्यांकन करेगा और दायित्वों की संगणना करेगा, अर्थात :-

(क) सरकारी प्रतिभूतियों से निम्न निषेधों का मूल्यांकन विहित तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख की विद्यमान बाजार बरों पर किया जाएगा ।

(ख) (i) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी अधिनियम अधिनियम, 1949 की धारा 24 के प्रयोजनार्थ निर्णित अधिसूचना में विहित मिश्रणों के अनुसार विहित तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख की स्थिति के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, जैसे डाकघर-प्रमाण पत्र, कोषागार बल्ल जमा प्रमाण-पत्र और केन्द्रीय सरकार की लक्ष्य वचन योजना के अधीन जारी की गयी किसी अन्य प्रतिभूतियों या प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य के आधार पर या उक्त तारीख को नकद प्राप्त मूल्य के आधार पर, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, किया जायेगा ।

(iii) जहां किसी सरकारी प्रतिभूति, जैसे जमींदारी उत्पन्न बंधपत्र या अन्य समान प्रतिभूति, जिसका मूलधन किम्ती में देय है का बाजार मूल्य अभिविधित नहीं किया जा सकता है या किसी कारणवश यह माना जाता है कि वह उसका उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करता है या वह अन्यथा उचित नहीं है, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन ऐसी रकम पर, जो मूलधन की किम्ती और देय शेष व्ययों के संबंध में उचित समझी जाये, उस कात्वाधि, जिसके दौरान ऐसी किम्ती देय है सरकार द्वारा जारी की गयी किसी प्रतिभूति के मूल्य और जिसकी गतता या नामग समान परिपक्वता है और अन्य सुवर्णन तर्कों के आधार पर किया जायेगा ।

(ग) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बंध-पत्र या अन्य निवेश का बाजार मूल्य उसके अवामान्य बाजार में प्रभावित हो जाये के कारण अक्षिपकन नहीं समझा जाय, वहां निवेश का मूल्यांकन किसी व्यक्तिगत कालावधि के दौरान उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जायेगा ।

(घ) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर या डिबेंचर या अन्य निवेश का बाजार मूल्य अभिविधित नहीं किया जा सकता है, वहां निर्णय संस्था की वित्तीय स्थिति, पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान

उनके द्वारा सेवित लाभों और अन्य मुनगल नग्यों की व्याप्ति रखते हुए केवल ऐसे मूल्य को, यदि हो, जो युक्तियुक्त समझा जाये, हिसाब में लिया जायेगा।

- (क) दावा की त्रुटि के लिए अर्जित परिमर्शों और अन्य सभी अचल संपत्तियों और आस्तियों का मूल्यांकन उनके वाजार मूल्य पर किया जायेगा।
- (ख) फर्निचर और फिक्चर, स्टॉक गत लेखन सामग्री और आस्तियाँ, यदि हों, का मूल्यांकन प्रति बड़ी ह्यामिन मूल्य या व्यक्तिव्यक्ति समझे जाने वाले बगुली योग्य मूल्य के आधार पर किया जायेगा।
- (ग) खरीदे और बनाये गये विल सहित ग्रिमो, बड़ी शृणों और फुटकर आस्तियों का खानदान अंतरिता बैंक द्वारा हो जायेगी और उनके आवरक के रूप में धारित प्रत्याभूत सहित प्रतिभूतियों का परीक्षण और सत्यापन भी अंतरिता बैंक द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् अधिम जिनके अन्तर्गत उनके भाग भी हैं दो श्रेणियों अर्थात् "अच्छा और सहज बसुली योग्य माने गये अधिम" और "सहज बसुली योग्य नहीं माने गये और या अशोध्य अथवा गदिरध बसुली वाले अधिम" में वर्गीकृत किये जायेंगे।

(II) इस योजना के प्रयोजनार्थ वास्तवों के अन्तर्गत ऐसी सभी आकस्मिक देयताएँ भी हों जिनकी विहित तारीख का या उसके पश्चात् अपने कोशों में उचित ह्रास से पूर्ण करने की आशा या अपेक्षा अंतरिता बैंक से की जा सकेगी।

(III) जहाँ किसी आस्ति का मूल्यांकन विहित तारीख का नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से अग्रतः या पूर्णतः किसी पश्चात्कर्ती तारीख का बसुली योग्य आस्ति के रूप में माना जायेगा। किसी आस्ति के मूल्यांकन और/या किसी अधिम के वर्गीकरण और/या किसी देयता के निवारण के संबंध में अंतरिता बैंक और अंतरक बैंक के बीच कोई असहमति हो, तो यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा, जिसकी राय अंतिम होगी, परन्तु जब तक ऐसी राय प्राप्त नहीं हो जाती तब तक अंतरिता बैंक द्वारा इस योजना के प्रयोजनार्थ किसी मद या उनके अंग का मूल्यांकन अंतिम रूप से किया जायेगा।

ऐसा करना आवश्यक होने की दशा में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए ऐसा तकनीकी परामर्श प्राप्त करना उचित होगा, जैसा वह आस्ति की ऐसी किसी मद के मूल्यांकन या देयता को ऐसी मद के निवारण के संबंध में उपयुक्त समझे और परामर्श प्राप्त करे। ता अन्य अंतरक बैंक आस्तियों में से पूर्ण रूप में हो होगा।

पुनर्गामी उपबंधों के अनुसार आस्तियों का मूल्यांकन और देयताओं का निवारण दोनों बैंकों और उनके संबंधों और लेनदारों पर बाध्यकारी होगा।

(5) अंतरिता बैंक को अंतरक बैंक की संपत्ति और आस्तियों के कारण के प्रतिफल स्वच्छ अंतरिता बैंक द्वारा निम्नलिखित खर्चों में उल्लिखित सीमा तक अंतरक बैंक के दावियों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

- (क) अंतरक बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा कर्मचारी प्रतिभूति निधि के रूप में उस बैंक में जमा कोई राशि और विहित तारीख तक उस पर प्राप्ति ब्याज, यदि हो तथा जमा राशि का शोषण विहित तारीख को सभी अन्य वाद्यों के दावियों की जायेगी या उसकी समायोजी का पूरी व्यवस्था की जाएगी।

समाप्ति

इस पैरा के प्रयोजन के लिए विहित तारीख तक किसी जमा राशि पर देय ब्याज संबंध जमा राशि का भाग माना जायेगा।

(ख) अंतरक बैंक में रखे प्रत्येक वक्षत बैंक खाते या चालू खाते या किसी अन्य निधि की बाबत जिनके अन्तर्गत सावधि जमा राशि नकदी प्रमाण पत्र, मासिक जमा राशि, मास या अन्य मुक्ता पर प्रतिवेद्य जमा राशि या किसी भी नाम से किसी अन्य जमा राशि और इस योजना के अंतर्गत देय सीमा तक ब्याज सहित किसी अन्य खाते जो खंड (क) के अंतर्गत नहीं आते हैं, के संबंध में अंतरिता बैंक उक्त आस्तियों में से यथामूल्यांकित उन अधिमों को, जो सहज बसुली योग्य नहीं समझे गये हैं, या अशोध्य अथवा बसुली के लिये गदिरध समझे गये हैं, विहित तारीख को अमूल्यांकित आस्ति या उसके किसी भाग को और उक्त खंड (क) में उल्लिखित भुगतान या प्रावधान के निम्न आवश्यक किसी राशि को घटाने के बाद तथा उक्त आस्तियों में अंतरक बैंक को निर्गत दिनांक 14 जुलाई 1990 के अधिस्थगन आदेश के पैरा 2 के खंड (क) (1) के अनुसार किये गये भुगतान को यथामूल्यांकित सकल राशि को घटाने के बाद विहित तारीख को इस स्कोम के प्रयोजनार्थ पैरा (4) में विनिर्दिष्ट और यथामूल्यांकित आस्तियों में से प्रत्येक खाते के संबंध में उपलब्ध आनुपातिक अंग के अनुसार राशि जमा करते हुए विहित तारीख का संबंधित धारक(कों) के नाम में प्राप्त बैंक में नगदान और वैसा ही खाना खोलेगा।

परन्तु 14 जुलाई, 1990 का काराबार की समाप्ति पर या उसके पश्चात् और विहित तारीख के पूर्व किसी जमा खाते से किए गए किसी भुगतान की संगणना इस उप पैरा के अधीन जमा की जाने वाली राशि के मद में की जाएगी और तदनुसार जमा की जाने वाली राशि जिनके ऐसे भुगतान की राशि कम कर दी जाएगी, आनुपातिक अंग होगी।

परन्तु यह और कि जहाँ अंतरिता बैंक को किसी विशेष खाते में की गयी प्रविष्टियों के सही होने के बारे में कोई उचित संदेह है तो वह रिजर्व बैंक के अनुमोदन से उक्त खंड (ग) के अनुसार उस लेखे में जमा की जाने वाली राशि रख सकेगा जब तक अंतरिता बैंक ऐसे खाते में सही जमा राशि अभिनिश्चित नहीं कर लेता।

स्पष्टीकरण

"आनुपातिक" पद में, जहाँ भी वह पैरा में आए, ऐसी संबंधित राशि के अनुपात से अभिप्रेत है, जो 14 जुलाई, 1990 को काराबार की समाप्ति पर विहित तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तारीख तक देय ब्याज सहित बकाया देय है और जहाँ भी वह इस योजना में अन्यत्र आए, ऐसी संबंधित राशि में अनुपात से अभिप्रेत है जो भुगतान या निवारण के समय बकाया देय है।

(ग) ऊपर खंड (ख) में विनिर्दिष्ट जमा राशि दिए जाने के पश्चात् अंतरिता बैंक यथासंभव कम बिन्दु से किन्तु विहित तारीख से तीन मास तक निधिपे कीमा और प्रत्येक भारतीय रिजर्व अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित निधिपे सीमा और रिजर्व गारंटी निगम को (जिसे इसमें इसके पश्चात् निगम कहा गया है), एक सूची देगा, उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पूर्ण अनुपालन करने हुए एक सूची प्रस्तुत करेगा और तत्पश्चात् जब कभी उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट राशि निगम में से प्राप्त हो, अंतरिता बैंक राशि प्राप्ति की तारीख या तारीखों से सात दिन के अंदर उस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अनुसार उस खाते में देय राशि की सीमा तक अन्य खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक खातों में राशि जमा करेगा परन्तु—

- (i) यदि खंड (ख) में निविष्ट कोई खाता बंद कर दिया गया है या वह उस खाते में जमा के लिए निगम से राशि की प्राप्ति के समय पर्याप्त हो गया है तो उस राशि का भुगतान उसके हकदार व्यक्ति को अंतरिती बैंक द्वारा नकदी में किया जायेगा।
- (ii) यदि खंड (ख) में निविष्ट किसी रकम के हकदार व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है या उसका आसानी से पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को वे राशि के लिए उपबंध किया जाएगा और उसका हिसाब अलग से निगम की बहियों में लिखा जाएगा तथा निगम के लिए अंतरिती बैंक को किसी राशि का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि रकम का हकदार व्यक्ति मिल नहीं जाता है या उसका पता नहीं चल जाता है और निगम अंतरिती बैंक के माध्यम से उस व्यक्ति के संबंध में भुगतान करने का विनिश्चय नहीं कर लेता।
- (ख) विहित तारीख को अंतरक बैंक की चुकता पुंजी और रिजर्व की पूरी राशि अंतरक बैंक के अधोध्य और संबद्ध ऋण और अन्य आस्तियों में ह्रास के लिये किये गये प्रावधान के रूप में मानी जाएगी तथा अंतरिती बैंक के संबंध में अंतरक बैंक के सदस्यों के अधिकार ऐसे होंगे जैसा नीचे पैरा '6' में उपबंधित है।
6. निम्नलिखित के संबंध में :-
- (क) पूर्ववर्ती पैरा के खंड (ख) में उल्लिखित प्रत्येक खाता उस खंड और खंड (ग) के अनुसार किसी खाते में, यदि है, जमा नहीं की गयी राशि और
- (ख) अंतरक बैंक में प्रत्येक शेयर की बाबत जिसकी रकम का विहित तारीख से ठीक पूर्व प्रत्येक शेयर धारक के द्वारा या उसकी ओर से शेयर पुंजी के मद्दे समावस्त रूप में माना गया था और या नीचे (1) के अनुसरण में अंतरिती बैंक द्वारा की गयी मांग के मद्दे रकम संदाय की गयी थी, संग्रहण लेख के रूप में माना जाएगा और उसे अंतरिती बैंक की बहियों में उसी प्रकार दर्ज किया जाएगा और लेखा में संदाय निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :-
- (1) (क) अंतरिती बैंक, प्रथमतः, ऐसे व्यक्ति से जो विहित तारीख को अंतरक बैंक में आस्थिति शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होता) ऐसी तारीख या तारीखों से तीन मास के अंदर जो निविष्ट की जाए ऐसे शेयर या शेयरों और बकाया मांगों, यदि कोई हों, की बाबत उसके द्वारा असंदत रह रही अनाहृत रकम का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा और तत्पश्चात् यदि यह आवश्यक पाया जाता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जो विहित तारीख को अंतरक बैंक के साधारण शेयरधारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होता ऐसी तारीख या तारीखों से जो निविष्ट की जाये, तीन मास के अंदर ऐसे शेयर या शेयरों का बकाया मांगों, यदि कोई हों, की बाबत उसके द्वारा असंदत रह रही अनाहृत रकम का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (ख) अंतरक बैंक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत (चूक की अवधि के लिए छः प्रतिशत वार्षिक ध्यान सहित खंड (क) के अधीन वे रकम में संदाय की मांग और उसे प्रवर्तित करने के लिए सभी संभव उपाय करेगा।
- (2) अंतरिती बैंक अधिमों, खरीदे या बट्टा लगाये गये विलों, बही ऋणों और विधिक ऋणों तथा अन्य आस्तियों की बाबत, जो "जिसे अधिमों के रूप में जो आसानी से बसूली योग्य नहीं है और या बसूली के लिए अधोध्य और बसूली की दृष्टि से संदिग्ध" हैं, के रूप में वर्गीकृत किया गया है : या जो ऊपर पैरा 1 के आधार पर विहित तारीख के पश्चात् पूर्णतः या अंशतः बसूली योग्य है या हो सकते हैं, के संबंध में मामलों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संदाय की मांग और उसे प्रवर्तित करने के लिए सभी उपलब्ध कार्यवाही करेगा, परन्तु यदि किसी ऋण या आस्ति की रकम 50,000 रुपये से अधिक है, तो अंतरिती बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना :
- (क) ऋणों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा या किसी ऐसे ऋण या आस्ति को बट्टे खाते नहीं खोलेगा।
- (ख) उसे अंतरित किसी प्रतिभूतियों का या उसके द्वारा की गयी किसी आस्ति का विषय या अन्य प्रकार से निपटान नहीं करेगा।
- (3) इनके अतिरिक्त, अंतरिती बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45-अ के साथ और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 543 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45-ड के अधीन अंतरिती बैंक के किसी संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा क्षति के रूप में अधिनिर्णय की गयी रकम, यदि कोई हो, की मांग करने और उनका संदाय करवाने के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी संभव कार्रवाई करेगा।
- (4) अंतरिती बैंक, उपर्युक्त खंड (1), (2) और (3) में उल्लिखित मामलों के कारण अपने द्वारा की गयी बसूलियों में से किसी समाधित वायित्व की बाबत, और रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से किसी ऐसे वायित्व, चाहे वह समाधित हो या अस्थायिक, की बाबत, जिसे उपर्युक्त पैरा (4) के निबंधनों के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था और जो विहित तारीख को या उसके पश्चात् उद्भूत हुआ है या जिसका पता चला है, संदाय कर सकेगा या उस सीमा तक, जो पैरा 45-क के अधीन उसके लिए किया गया प्रावधान अपर्याप्त हो, प्रावधान कर सकेगा।
- (5) अंतरिती बैंक, उपर्युक्त खंड (1), (2) और (3) में उल्लिखित मामलों के कारण अपने द्वारा की गयी बसूलियों में से, उस प्रयोजन के लिए किये गए व्यय हेतु और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से ऐसे अन्य व्ययों के लिए जो उचित समझे जायें, उनमें से कटौती करने और उपर्युक्त खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार उनमें से रकम विनियोजित करने के पश्चात् या ऐसी शेष राशि, यदि कोई हों, में से, जो ऐसे वायित्वों की सीमा अंतिम रूप से अभिनिश्चित की जाने के पश्चात् इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए यथा संगणित समाधित वायित्वों की बाबत प्रावधान में से उपलब्ध हों,
- (क) निधेय बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन अंतरिती बैंक द्वारा निगम से प्राप्त रकम और निगम द्वारा प्रावधान की गयी रकम, यदि कोई हो, का संदाय करेगा, और

(ख) ऐसे निक्षेपकर्ताओं के मामले में, जिनकी बाबत अंतरिती बैंक द्वारा कोई रकम निगम में प्राप्त नहीं की गयी है, संग्रहण खाते की बाबत शोध्य रकमों का, और ऐसे निक्षेपकर्ताओं के मामले में जिनकी बाबत अंतरिती बैंक द्वारा कोई रकम निगम में प्राप्त की गई है या निगम द्वारा उसका प्रावधान किया गया है, निगम द्वारा किए गए प्रावधान या संदाय की बाबत निगम को उक्त खाते में शोध्य रकमों की उपर्युक्त उपखंड (क) के उपबन्धों के अनुसार पहले संवत् किए जाने के पश्चात् उनके संग्रहण खाते में उन्हें शोध्य अनिवेष्ट, यदि कोई हो, का संदाय करेगा।

परंतु यह कि निगम को शोध्य रकम, यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो, अंतरिती बैंक की बहियों में उपवर्धित की जाएगी तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम अधारण विनियम, 1961 के विनियम 22 या इस (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से निगम को सदाय की जाएगी।

परंतु यह और कि अंतरिती बैंक, उपर्युक्त खंड (ख) में विनिर्दिष्ट संदाय उस क्षण में करेगा —

- (1) यदि पैरा (5) के खंड (ख) में उल्लिखित वर्तमान या समरूप खाते को बंद नहीं किया गया है या वह उस खाते में प्रत्यक्ष द्वारा भुगतान के लिए परिपक्व नहीं हुआ है, और
- (2) यदि उक्त खाते को बंद कर दिया गया है या वह नकद भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है।
- (3) उपर्युक्त खंड (5) के उपखंड (क) के अनुसार निगम को शोध्य रकमों और उस खंड के उपखंड (ख) के अनुसार निक्षेपकर्ताओं के संग्रहण खाते में शोध्य रकमों की धेणी आपस में समान होगी, और यदि उनका संशय पूर्णतः नहीं किया जा सकता तो उनमें समान अनुपात में कमी होगी।
- (4) इस पैरा के खंड (5) में निर्दिष्ट संदाय कर दिये जाने या उसके लिए पूर्ण प्रावधान कर दिये जाने के पश्चात्, अंतरिती बैंक, खंड (5) में निर्दिष्ट रकमों में से शेष राशि, जो उसके पास उपलब्ध हो, से तो, अंतरक बैंक के भूतपूर्व शेयरधारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो, हेतु ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नीचे विनिर्दिष्ट है, आनुपातिक संदाय करेगा,
- (क) प्रथमतः, सब खातों के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक अंतरक बैंक के भूतपूर्व अधिमान शेयरधारकों के खाते में उन्हें देय रकम, यदि कोई हो,
- (ख) द्वितीयतः, सब खातों के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक अंतरक बैंक के भूतपूर्व सामान्य शेयरधारकों के खाते में उन्हें देय रकम, यदि कोई हो और उसके पश्चात्
- (ग) तृतीयतः, सब खातों के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक अंतरक बैंक के भूतपूर्व आस्थगित शेयरधारकों के खाते में उन्हें देय रकम, यदि कोई हो,
- (घ) उपर्युक्त उपखंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित सभी राशियां पूर्णतः संवत् करने के पश्चात् अंतरिती बैंक के पास बाकी बचे अधिशेष का अंतरक बैंक के भूतपूर्व सामान्य शेयरधारकों के बीच आनुपातिक वितरण किया जाएगा।

परंतु यह कि यदि यह प्रकट उठता है कि उपर्युक्त किसी उपखंड में उल्लिखित खाते के लिए कोई रकम देय है या नहीं, तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिष्कण प्रभाव होगा।

(8) इस पैरा में निर्दिष्ट संग्रहण खाते में देय रकम के बारे में केवल अंतरिती बैंक का वायित्व उस सीमा तक समझा जाएगा, जिसका इस स्कीम में प्रावधान है।

(9) विहित मानीय में आरह वर्ष या भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के पश्चात् भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट इससे कम अधिशेष के बीतने पर, इस पैरा के खंड (2) में उल्लिखित किसी भी ऐसी मद का, जो उस तारीख तक वसूल नहीं की जा सकी हो, मूल्यांकन अंतरिती बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से किया जाएगा और अंतरिती बैंक, उक्त मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, अवधारित कोई रकम इस पैरा के खंड (4) में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक किसी ऐसी राशि को, जो उपर्युक्त खंड (5), (6) और (7) में उपवर्धित क्रम और नीति से उस तारीख तक चुकायी जाने से रह गयी हो, पहले उनमें से कटौती करके वितरित करेगा,

(10) अंतरिती बैंक, पूर्ववर्ती खंड (1), (2) और (3) में उल्लिखित मदों के कारण वसूल किए गए ऐसे अंश का, जिनके तुरंत संदाय के लिए उसके द्वारा अपेक्षा किए जाने की संभावना नहीं है, अपने पास या किसी अन्य बैंक या बैंकों के पास व्याज वाले निक्षेपों में, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त हो या जैसा भारतीय रिज़र्व बैंक निदेश दे, निवेश करेगा। प्रोद्भूत व्याज को खंड (4), (5), (6) और (7) में निर्दिष्ट दायित्वों की पूर्ति के लिए उनमें उपवर्धित रीति से उपयोजित किया जाएगा।

7. किसी अभिध्यक्ष या विवक्षित संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होने हुए भी, पैरा (5) के निर्बंधनों के अनुसार अंतरिती बैंक के पास पास खोले गए गए खाते की बाबत व्याज का संदाय किया जाएगा और उसमें केवल उन या अगले उत्तरवर्ती परामर्शों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी दरों पर, जो अंतरिती बैंक अनुज्ञात करे, जमा किया जाएगा।

8 अंतरक बैंक का कोई भी निक्षेपकर्ता या अन्य लेनदार, उसके प्रति अंतरक बैंक के किसी दायित्व की बाबत अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक से इस स्कीम द्वारा विहित सीमा तक निधान, कोई मांग करने का हक्कदार नहीं होगा।

9 केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक या अंतरिती या अंतरक बैंक के खिलाफ ऐसी किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी, जो इस स्कीम के अनुसरण में सम्भावपूर्वक की गयी है या जिसके करने की इच्छा है।

10 अंतरक बैंक के सभी कर्मचारी राधा में बने रहेंगे और यह समझा जाएगा कि उन्हें अंतरिती बैंक द्वारा उभी पारिश्रमिक और सेवा के उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया गया है जो 14 जुलाई 1990 की तारीख तक होने के ठीक पहले ऐसे कर्मचारियों को लागू था।

परंतु यह कि अंतरक बैंक के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक को, उस तारीख के, जिसको यह स्कीम के अधीन सरकार द्वारा सत्र की गयी है, ठीक आगामी एक मास के अवधान के पूर्व किसी भी समय अंतरिती बैंक के कर्मचारी न होने का अपने पाण्डों के बारे में लिखित सूचना द्वारा सूचित किया है, आयोगिक विवाद प्रक्रियामय, 1947 के उपबन्धों के अधीन ऐसी अनिर्णित, यदि कोई हो, और ऐसी पेशवा, उत्पन्न भविष्य निधि और मेरिटानिष्ठि लाभ के संदाय के लिए हकदार होंगे, जो 14 जुलाई 1990 की तारीख तक होने के ठीक पहले अंतरक बैंक के अधिकरण नियमों के अधीन सामान्य तौर पर अनुज्ञेय हो।

परन्तु यह और कि योग्य बैंक के ऐसे कर्मचारियों की बाबत, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक के बारे में भी यह समझा जाएगा कि उनमें अंतर्राष्ट्रीय बैंक की सेवा में रहने के दौरान उनकी छुट्टी की वृद्धि में इस आधार पर छूटना संबंधी धनपूर्ति के सहाय का दायित्व दिया है कि उनकी सेवा निरंतर बनी रही है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उनके स्थानान्तरण में विघटन नहीं हुई है।

11. अंतर्राष्ट्रीय बैंक, उस तारीख से जिस तारीख को इस स्कीम की मंजूरी किया जाता है, तीन वर्षों से गतवर्षीय गवर्निंग के अयमान पर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारियों को वही पारिश्रमिक और सेवा के वही नियम और शर्तें प्रदान या मंजूर करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक के तत्समान श्रेणी (रेक) या स्तर के कर्मचारियों को, अंतर्राष्ट्रीय बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों के समान या समानुपात अंतर्राष्ट्रीय बैंक के उक्त कर्मचारियों के पास अर्हताएं और अनुभव के अभाव रहते हुए, लागू हों।

परन्तु यह कि यदि इस तार में कोई शर्त या मतभेद उत्पन्न होता है कि उक्त कर्मचारियों में से किसी को अर्हताएं या अनुभव अंतर्राष्ट्रीय बैंक के तत्समान श्रेणी (रेक) या स्तर के अन्य कर्मचारियों को अर्हताएं और अनुभव के समान या समानुपात है या नहीं या वह अंतर्राष्ट्रीय बैंक के तत्समान में कर्मचारियों का दायित्व निभाने करने के लिए अपनाये जानेवाले विधानों की पड़िया के संबंध में है, तो शर्त या मतभेद को भारतीय रिजर्व बैंक को निरिद्ध किया जाएगा, जिसका उग पर अनिच्छा (निर्णय) अंतिम होगा।

12. पदास्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बैंक या अंतर्राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारियों के लिए, यदि किसी भविष्य तिथि और/या उपदान तिथि के न्यासी या पदास्थिति, विहित तारीख को या उसके पश्चात् पदास्थिति और, अंतर्राष्ट्रीय बैंक के लिए, यदि किसी भविष्य तिथि और/या उपदान तिथि के न्यासी को, या अन्यथा, जैसा अंतर्राष्ट्रीय बैंक निर्देश दे, अंतर्राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारियों के पावते के लिए, न्यास में धारित सख्त और विनिश्चित अंतर्निहित कर देंगे।

परन्तु यह कि ऐसे पदास्थिति न्यासी, विनिश्चित के रूप में किसी कमी के लिए, या विहित तारीख में पढ़ने किए गए, किसी कार्य, उपेक्षा या त्यागपत्र की बाबत उत्तरदायी नहीं होंगे।

13. अंतर्राष्ट्रीय बैंक ऐसे विवरण और जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को भेजेगा, जिसकी भारतीय रिजर्व बैंक इस स्कीम के कार्यान्वित करने के संबंध में समय-समय पर अपेक्षा करे।

14. अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक के कार्यकलाप का विवरण, ऐसे प्रारूप में और ऐसे कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, अंतर्राष्ट्रीय बैंक के नियंत्रणों को भेजेगा। ऐसे विवरणों का भेजा जाना तब तक जारी रहेगा जब रिजर्व बैंक ऐसा निर्देश दे।

15. किसी ऐसी सूचना या अन्य सूचना के बारे में जिसके लिए जाने की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय बैंक से की जाती है, उस वृत्ति में सूचना यदि दी गयी समझा जाएगा जब अंतर्राष्ट्रीय बैंक को पुस्तकों में लिखे हुए, पत्र पर, जब तक कि कोई नया पत्र अंतर्राष्ट्रीय बैंक की पुस्तकों में न लिखा जाये, प्रेषित की संशोधित किया गया हो और उस पूर्व-सदस्य सामान्य ढाँचे में भेज दिया गया हो, और ऐसी सूचना तक में जाने के पश्चात्/अधस्तात् छप्पे धोवन पर तभीक की गयी समझी जाएगी। इसके अतिरिक्त, किसी ऐसी सूचना या सूचना को, जो सांकेतिक तित हो हो, एक या अधिक दैनिक समालोचकों में, जिसका परिभाषित क्षेत्र स्थान पर हो उस बैंक पास कारोबार या संवर्धन कर रहा था, निशानित किया जाएगा।

16. यदि इस स्कीम के अन्तर्गत या अन्तर्गत करने समझा जाये, शर्तों के अन्तर्गत हो तो सामग्री को भारतीय रिजर्व बैंक को निरिद्ध

किया जाएगा और उसकी राय अंतिम होगी और अंतर्राष्ट्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दोनों पर तथा इस प्रत्येक बैंक के सभी सदस्यों, निदेशपक्षियों और अन्य नियंत्रणों तथा कर्मचारियों पर भी और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर, जिसका इन बैंकों में से किसी के मदद में कोई अधिकार या दायित्व है, बाध्यकारी होगी।

17. यदि इस स्कीम के उपबंधों का प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को या उनमें से किसी को, ऐसे निर्देश जारी कर सकती जो इस स्कीम से असंगत न हों, और जो केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रभावित।

[स. 17/7/89-बी.ओ. 111(ii)]

एन. एन. मुखर्जी सचिव सचिव

S.O. 661(E).—Whereas on an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government has made, under sub-section (2) of the said Section 45 an order of moratorium in respect of the Purbanchal Bank Ltd., under sub-section (2) of the said section.

And whereas the Reserve Bank of India in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 45 of the said Act has prepared a scheme for the amalgamation of the Purbanchal Bank Ltd., with the Central Bank of India.

And whereas the Reserve Bank of India after having sent the said scheme in draft to the banks concerned in accordance with the provisions of sub-section (6) of the said section and after having considered the suggestions and objections received in regard to the said scheme had modified that scheme and forwarded it to the Central Government for sanction.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 45 of the said Act, the Central Government hereby sanctions the scheme on and subject to the terms and conditions hereinafter mentioned.

(1) The Purbanchal Bank Ltd., shall be the transferor bank and the Central Bank of India shall be the transferee bank.

(2) As from the date which the Central Government may specify for this purpose under sub-section (7) of Section 45 of the said Act (hereinafter referred to as the prescribed date) all rights, powers, claims, demands, interests, authorities, privileges, benefits, assets and properties of the transferor bank, movable and immovable, including premises subject to all incidents of tenure and to the rents and other sums of money and covenants reserved by or contained in the leases or agreements under which they are held, all office furniture, loose equipment, plant apparatus and appliances, books, papers, stocks of stationary, other stocks and stores all investments in stocks, share and securities, all bills receivable in hand and in transit, all cash in hand and on current or deposit account (including money at call or short notice) with banks, bullion, all book debts, mortgage debts and other debts with the benefit of securities, or any guarantee therefore, all other, if any, property rights and assets benefit of all guarantees in connection with the business of the transferor bank shall, subject to the other provisions of this scheme, stand transferred to, and become the properties and assets of, the transferee bank; and as from the prescribed date all the liabilities, duties and obligations of the transferor bank shall be and shall become the liabilities, duties and obligations of the transferee bank to the extent and in the manner provided hereinafter.

Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting at having effect immediately before the prescribed date shall be effective to the extent and in the manner hereinafter provided against or

in favour of the transferee bank and may be acted upon as if instead of the transferor bank the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank.

If on the prescribed date any suit, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the transferor bank is pending, the same shall not abate, or be discontinued or be in any way prejudicially affected, but shall subject to the other provisions of this scheme, be prosecuted and enforced by or against the transferee bank.

If according to the laws of any country outside India the provisions of this scheme, by themselves, are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor bank to or in the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such assets or liability shall, on the prescribed date, stand entrusted to the chief executive officer for the time being of the transferee bank and the chief executive officer may exercise all powers and do all such acts and things as would have been exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively winding up its affairs. The chief executive officer shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of affecting such transfer or vesting and in connection therewith the chief executive officer may, either himself or through any person authorised by him in this behalf, realise any assets or discharge any liability of the transferor bank and transfer the net proceeds thereof to the transferee bank.

(3) The books of the transferor bank shall be closed and balanced and balance sheets prepared in the first instance as at the close of business on the 14th July 1990 and thereafter as at the close of business on the date immediately preceding the prescribed date. The balance sheets as on the date preceding the prescribed date shall be got audited and certified by a chartered accountant or a firm of chartered accountants approved or nominated by the Reserve Bank of India for the purpose.

A copy each of the balance sheets of the transferor bank prepared in accordance with the provisions of the foregoing paragraph, shall be filed by the transferor bank with the Registrar of Companies as soon as possible after it has been received and thereafter the transferor bank shall not be required to prepare balance sheets or profit and loss accounts, or to lay the same before its members or file copies thereof with the Registrar of Companies or to hold any annual general meeting for the purpose of considering the balance sheet and accounts or for any other purpose or to comply with the provisions of Section 159 of the Companies Act, 1956, and it shall not thereafter be necessary for the Board of Directors of the transferor bank to meet as required by Section 285 of that Act.

(4) (i) The transferee bank shall, in consultation with the transferor bank, value the property and assets and reckon the liabilities of the transferor bank in accordance with the following provisions, namely :—

(a) Investments other than Government Securities shall be valued at the market rates prevailing on the day immediately preceding the prescribed date.

(b) (i) Government Securities shall be valued as on the day immediately preceding the prescribed date in accordance with the principles laid down in the notification issued by Reserve Bank of India for the purpose of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949.

(ii) The Securities of the Central Government such as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued under the small savings scheme of the Central Government shall be valued at their face value or the encashable value as on the said date, whichever is higher.

(iii) Where the market value of any Government security such as The Zamindari Abolition Bonds or other similar security in respect of which the principal is payable in instalments is not ascertainable or is, for any reason, not

considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such an amount as is considered reasonable having regard to the instalments of principal and interest remaining to be paid, the period during which such instalments are payable, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity, and other relevant factors.

(c) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period.

(d) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not ascertainable only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of the issuing concern, the dividends paid by it during the preceding five years and other relevant factors.

(e) Premises and all other immovable properties and any assets acquired in satisfaction of claims shall be valued at their market value.

(f) Furniture and fixtures, stationery in stock and other assets, if any, shall be valued at the written down value as per books or the realisable value as may be considered reasonable.

(g) Advances including bills purchased and discounted bank debts and sundry assets, will be scrutinised by the transferee bank and the securities, including guarantees, held as cover therefore examined and verified by the transferee bank. Thereafter the advances, including portions thereof, will be classified into two categories namely, "Advances considered good and readily realisable" and "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful of recovery".

(II) Liabilities for purposes of this scheme shall include all contingent liabilities which the transferee bank may reasonably be expected or required to meet out of its own resources on or after the prescribed date.

(III) Where the valuation of any asset cannot be determined on the prescribed date, it may, with the approval of the Reserve Bank of India be treated partly or wholly as an asset realisable at a later date.

In the event of any disagreement between the transferee bank and the transferor bank as regards the valuation of any asset and/or the classification of any advance and/or the determination of any liability, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India, whose opinion shall be final provided that until such an opinion is received, the valuation of the item or portion thereof by the transferee bank shall provisionally be adopted for the purpose of this scheme.

It shall be competent for the Reserve Bank of India in the event of its becoming necessary to do so, to obtain such technical advice as it may consider to be appropriate in connection with the valuation of any such item of asset or determination of any such item of liability, and the cost of obtaining such advice shall be payable in full out of the assets of the transferor bank.

The valuation of the assets and the determination of the liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be binding on both the banks and the members and creditors thereof.

(5) In consideration of the transfer of the property and the assets of the transferor bank to the transferee bank, the transferee bank shall discharge the liabilities of the transferor bank to the extent mentioned in this and the following clauses, namely,

(a) Any sums deposited by any employee of the transferor bank with that bank as staff security deposits together with interest, if any, accrued thereon upto the prescribed date and all other outside liabilities as on the prescribed date excluding deposits shall be paid or provided for in full

EXPLANATION :

For the purpose of this paragraph, interest payable on a deposit upto the prescribed date shall be regarded as part of the concerned deposit.

(b) in respect of every savings bank account or current account or any other deposit including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposit by whatever name called with the transferor bank and every other account not covered by clause (a), including interest to the extent payable under this scheme, the transferee bank shall open with itself on the prescribed date a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto the pro rata share available in respect of each of the accounts out of the assets referred to in paragraph (4) as valued for the purposes of this scheme on the prescribed date, after excluding from the said assets as so valued the advances considered not readily realisable or bad or doubtful of recovery, any asset or portion of an asset not valued on the prescribed date and any amount needed for the payments or provisions mentioned at clause (a) above and after adding to the said assets as so valued the aggregate amount of the payments made in terms of clause (a) (i) of paragraph 2 of the moratorium order dated the 14th July 1990 issued to the transferor bank.

Provided that any payment made from a deposit account on, or after the close of business on 14th July 1990 and before the prescribed date, shall be reckoned towards the amount to be credited under this sub-paragraph and, accordingly the amount to be credited shall be the pro rata share less the amount of such payment.

Provided further that where the transferee bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account it may with the approval of the Reserve Bank, withhold the credit to be made in that account in terms of clause (b) above till the transferee bank is able to ascertain the correct balance in such accounts.

EXPLANATION

The term 'pro rata' shall, insofar as it occurs in this paragraph, mean in proportion to the respective amounts remaining due as at the close of business on the 14th July 1990 together with the interest payable upto the date immediately preceding the prescribed date and shall, insofar as it occurs elsewhere in this Scheme, mean 'in proportion to the respective amounts remaining due at the time of the payment or distribution'.

(c) After the credits referred to in clause (b) above have been afforded, the transferee bank shall, with the least possible delay but in any case not later than three months from the prescribed date, furnish to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (hereinafter referred to as the Corporation) a list complying in all respects with the requirements of sub-section (1) of Section 18 of that Act and thereafter whenever amounts referred to in sub-section (2) of Section 18 of that Act are received from the Corporation, the transferee bank shall credit each of the accounts referred to in clause (b) above, within seven days from the date or dates on which the amounts are received, to the extent of the sums due to that account in accordance with sub-section (2) of Section 18 of that Act :

Provided that—

(i) If any account referred to in clause (b) above has been closed or has matured for payment at the time when any amount for credit to that account is received from the Corporation, the payment to the person entitled to the said amount shall be made by the transferee bank in cash; (ii) In case the person entitled to any amount referred to in clause (b) above cannot be found or is not readily traceable, provision for the amount due to such person shall be made and accounted for separately on the books of the Corporation itself and it shall not be necessary for the Corporation to pay the amounts to the transferee bank

unless the person entitled to the amount is found or traced and the Corporation has decided to make the payment in respect of that person through the transferee bank. (d) On the prescribed date, the entire amount of the paid-up capital and reserves of the transferor bank shall be treated as provision for bad and doubtful debts and depreciation in other assets of the transferor bank and the rights of the members of the transferor bank shall, in relation to the transferee bank, be as provided for in paragraph (6) below :—

(6) In respect of

(A) every account mentioned in clause (b) of preceding paragraph, the balance in the account, if any, remaining uncredited in terms of that clause and clause (c) and

(B) every share in the transferor bank, the amount of which was treated as paid-up towards share capital by or on behalf of each shareholder immediately before the prescribed date and/or the amount paid on account of the calls made by the transferee bank in pursuance of clause (i) below :

shall be treated as a collection account and shall be entered as such in the books of the transferee bank and payments against the account shall be made in the following manner, namely :

(i) (a) the transferee bank shall, in the first instance, call upon every person who on the prescribed date was registered as the holder of a deferred share in the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares and the calls in arrears, if any and thereafter, if it is found to be so necessary, every person who was, as on the prescribed date, registered as the holder of an ordinary share of the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares or the calls in arrears, if any; (b) the transferee bank shall take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts due under clause (a) above to ether with interest at six per cent per annum for the period of the default.

(ii) the transferee bank shall in respect of the advances, bills purchased and discounted, book debts and Sundry debts and other assets, which are classified as "Advances considered not readily realisable and/or bad or doubtful of recovery", or which are or may be realisable wholly or partly after the prescribed date in terms of paragraph (4) above, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce payment, provided, however that if the amount of a debt or asset exceeds Rs. 50,000, the transferee bank shall not except with the approval of the Reserve Bank of India, (a) enter into a compromise or arrangement with the debtor or any other person or write off any such debt or asset,

(b) sell or otherwise dispose of any securities transferred to it or any asset taken over by it.

(iii) the transferee bank shall in addition take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts, if any, awarded as damages by the High Court against any promoter, director, manager or other officer of the transferor bank under Section 45L of the Banking Regulation Act, 1949, read with Section 45H thereof and also with Section 543 of the Companies Act, 1956;

(iv) the transferee bank may, out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in clauses (i), (ii) and (iii) above, make payment or provision in respect of any contingent liability to the extent that the provision made therefore under paragraph (5)(a) proves to be inadequate, as also with the prior approval of the Reserve Bank, in respect of any liability whether contingent or absolute which was not assessed in terms of para-

graph (4) above and has arisen or been discovered on or after the prescribed date;

(v) the transferee bank shall out of the realisations effected by it on account of the items mentioned in clauses (i), (ii) and (iii) above, after deducting there from the expenditure incurred for the purpose and, with the approval of the Reserve Bank of India, such other expenses as may be considered reasonable and the amount appropriated therefrom in terms of clause (iv) above, or out of the balance, if any, which may be available from out of the provisions in respect of contingent liabilities as reckoned for the purposes of this scheme after the extent of such liabilities has finally been ascertained.

(a) pay to the Corporation the amount received by the transferee bank from the Corporation under sub-section (2) of Section 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, and the amount, if any, provided for by the Corporation, and

(b) pay, in the case of depositors in respect of whom no amounts have been received by the transferee bank from the Corporation, the amounts due in respect of the collection accounts, and in the case of depositors in respect of whom any amounts have been received by the transferee bank from the Corporation or have been provided for by the Corporation the balance if any due to them in their collection accounts after the amounts due from the said accounts to the Corporation in respect of the payment made or provided for by the Corporation have first been paid in accordance with the provisions of sub-clause (a) above :

Provided that the amount due to the Corporation shall, if it becomes necessary so to do, be provided for in the books of the transferee bank and be paid to the Corporation in the manner specified in clause (b) of regulation 22 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

Provided further that the transferee bank shall make the payments referred to in clause (b) above,

(i) if the corresponding or similar account mentioned in clause (b) of paragraph (5) has not been closed or has not matured for payment, by credit to that account, and

(ii) if the said account has been closed or has matured for payment, in cash ;

(vi) The amounts due to the Corporation in terms of sub-clause (a) of clause (v) above and the amounts due to the collection accounts of the depositors in terms of sub-clause (b) of that clause shall rank equally amongst themselves, and if they cannot be paid in full shall abate in equal proportions ;

(vii) After the payments referred to in clause (v) of this paragraph have been made or provided for in full, the transferee bank shall, out of the balance of the amounts referred to in clause (v) which may be available to it, make payments pro rata towards the amounts, if any, due to the accounts of the former shareholders of the transferor bank in the manner and to the extent specified below :

(a) in the first place, the amounts, if any due to the accounts of the former preference shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made ;

(b) in the second place, the amount, if any, due to the accounts of the former ordinary shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made; and thereafter

(c) in the third place, the amounts, if any, due to the accounts of the former deferred shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made;

(d) after all the amounts mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c) above have been paid in full, the surplus, if any, remaining in the hands of the transferee bank shall be distributed pro rata among the former ordinary shareholders of the transferor bank.

Provided that if any question arises whether any amounts are due against an account mentioned in any of the above sub-clauses, it shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(viii) the amounts due to the collection accounts referred to in this paragraph shall be deemed to be a liability of the transferee bank only to the extent provided for in this scheme;

(ix) on the expiry of twelve years from the prescribed date or such earlier period as the Central Government after consulting the Reserve Bank of India may specify for this purpose, any item referred to in clause (ii) of this paragraph which may not have been realised by that date shall be valued by the transferee bank in consultation with the Reserve Bank of India and the transferee bank shall distribute any amount of amounts determined in the light of that valuation after deducting therefrom first any sum necessary for meeting the liabilities referred to in clause (iv) of this paragraph which may remain unsatisfied as on that date in the order and the manner provided in clauses (v), (vi) and (vii) above.

(x) The transferee bank shall invest such moneys realised on account of items mentioned in the preceding clauses (i), (ii) and (iii) as are not likely to be required by it for immediate payment, in interest bearing deposits with itself or with any other bank or banks, in such manner and for such periods as may be appropriate having regard to the facts and circumstances of the case or as the Reserve Bank of India may direct. The interest accrued shall be applied for meeting the liabilities referred to in clauses (iv), (v) (vi) and (vii) in the manner indicated therein.

(7) Notwithstanding anything to the contrary contained in any contract, express or implied, interest shall be paid in respect of the new accounts opened with the transferee bank in terms of paragraph (5) and credited in accordance with the provisions of that or the next succeeding paragraphs and at such rates as the transferee bank may allow.

(8) No depositor or other creditor of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent prescribed by this scheme.

(9) No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government, the Reserve Bank of India or the transferee or the transferor bank for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this scheme.

(10) All the employees of the transferor bank shall continue in service and be deemed to have been appointed by the transferee bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service as were applicable to such employees immediately before the close of business on 14th July, 1990 :

Provided that the employees of the transferor bank who have, by notice in writing given to the transferor or the transferee bank at any time before the expiry of one month next following the date on which this scheme has been sanctioned by the Central Government, intimated their intention of not becoming employees of the transferee bank, shall be entitled to the payment of such compensation, if any, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 and such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefit as may be ordinarily admissible under the rules of authorisations of the transferor bank immediately before the close of business on 14th July, 1990.

Provided further that the transferee bank shall in respect of the employees of the transferor bank who are deemed to have been appointed as employees of the transferee bank

be deemed to also to have taken over the liability for them of retrenchment compensation in the event of their being retrenched while in the service of the transferee bank on the basis that their service has been continuous and has not been interrupted by their transfer to the transferee bank.

(11) The transferee bank shall, on the expiry of a period not longer than three years from the date on which this scheme is sanctioned, pay or grant to the employees of the transferor bank the same remuneration and the same terms and conditions of service as are applicable to the employees of corresponding rank or status of the transferee bank subject to the qualifications and experience of the said employees of the transferor bank being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank.

Provided that if any doubt or difference arises as to whether the qualifications or experience of any of the said employees are the same as or equivalent to the qualifications and experience of the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank or as to the procedure of principles to be adopted for the fixation of the pay of the employees in the scales of pay of the transferee bank, the doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

(12) The trustees or administrators of any provident fund and/or gratuity fund constituted for the employees of the transferor bank or as the case may be the transferor bank shall on or as soon as possible after the prescribed date transfer to the trustee of the employees provident fund and/or gratuity fund constituted for the transferee bank, or otherwise as the transferee bank may direct, all the moneys and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank.

Provided that such latter trustees shall not be liable for any deficiency in the value of investments, or in respect of any act, neglect, or default done before the prescribed date.

(13) The transferee bank shall submit to the Reserve Bank of India such statements and information as may be

required by the Reserve Bank of India from time to time regarding the implementation of this scheme.

(14) The transferee bank shall furnish to the shareholders of the transferor bank a statement of affairs of the transferor bank in such form and at such periodical intervals as the Reserve Bank of India may specify in this behalf. The sending of such statements shall be discontinued when so directed by the Reserve Bank.

(15) Any notice or other communication required to be given by the transferee bank shall be considered to be duly given if addressed and sent by pre-paid ordinary post to the addressee at the address registered in the books of the transferor bank, until a new address is registered in the books of the transferee bank, and such notice shall be deemed to be served on the expiry of forty eight hours after it has been posted. Any notice or communication which is of general interest shall be advertised in addition in one or more daily newspapers which may be in circulation at the places where the transferor bank was transacting its business.

(16) If any doubt arises in interpreting any of the provisions of this scheme, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India and its opinion shall be conclusive and binding on both the transferee and transferor banks, and also on all the members, depositors and other creditors and employees of each of these banks and on any other places where the transferor bank was transacting its business.

(17) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this scheme, the Central Government may issue to the transferor and the transferee banks or to either of them such directions not inconsistent with this scheme as may appear to the Central Government, after consulting the Reserve Bank of India, to be necessary or appropriate for the purpose of removing the difficulty.

[No. 17/7/89-B.O. III (ii)]

N. N. MOOKERJEE, Jt. Secy.